3 प्राकृतिक नही मानव निर्मित है बाढ़.की आपदाएं

5 धर्म और राष्ट्र सेवा के विचारों से प्रभावित

7 पर्यावरण संरक्षण में वैश्विक योगदान

RNI-MPBIL/2011/39805

निष्पक्ष और निर्भीक साप्ताहिक

जगत प्रवाह

वर्ष : 16 अंक : 13 प्रति सोमवार, 4 अगस्त 2025 मूल्य : दो रुपये पृष्ठ : 8

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की एक महीना लंबी "शुभारंभ यात्रा"

कार्यकर्ताओं और जिला स्तर के नेताओं में मन में सवाल- आखिर भाजपा की रणनीति और संगठन की संरचना में कब आयेगी गति?

कवर स्टोरी

-विजया पाठक
एडिटर

हेमंत खंडेलवाल को मध्यप्रदेश भाजपा का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त हुए एक महीना पूरा होने को आया है। यह समयावधि किसी भी नए अध्यक्ष के लिए संगठन को दिशा देने, रणनीति तय करने और कार्यकारिणी के गठन की प्रक्रिया को गति देने के लिए महत्वपूर्ण होती है। किंतु अभी तक खंडेलवाल केवल नेताओं, कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से "शिष्टाचार मुलाकातों" तक ही सीमित रहे हैं। कार्यकर्ताओं में उत्साह तो है पर स्पष्ट दिशा नहीं दिख रही। यह प्रश्न तेजी से उभर रहा है कि क्या खंडेलवाल संगठनात्मक कसौटी पर खरे उतर पाएंगे?

न प्रदेश कार्यकारिणी बनी, न निगम-मंडलों में नियुक्तियाँ हुईं

एक महीना होने को है लेकिन अभी तक प्रदेश कार्यकारिणी का गठन नहीं हो पाया है। इसके अलावा राज्य के विभिन्न निगम-मंडलों में भाजपा की सरकार होते हुए भी राजनीतिक नियुक्तियों की गति शून्य जैसी बनी हुई है। यह सवाल आम कार्यकर्ताओं से लेकर जिला स्तर के नेताओं तक के बीच गूंज रहा है कि आखिर संगठन की संरचना को कब गति मिलेगी? प्रदेश कार्यकारिणी का गठन केवल औपचारिकता नहीं होता, बल्कि यह संगठन का रीढ़ होता है। प्रदेश के सभी क्षेत्रों से संतुलित प्रतिनिधित्व और सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए इस गठन की प्रतीक्षा की जा रही है। कार्यकारिणी ही नीतिगत दिशा तय करती है और आगामी चुनावी रणनीति की जमीन तैयार करती है। ऐसे में इसकी देरी पार्टी की गति को बाधित कर रही है। (शेष पेज 6 पर)

आखिर कब खुलेंगी कांग्रेस आलाकमान की आंखें, कमलनाथ की अनदेखी पड़ेगी भारी

कमलनाथ की नेतृत्व क्षमता और छिंदवाड़ा मॉडल बना भाजपा के विकास का आधार

-विजया पाठक

मध्यप्रदेश की राजनीति में अगर कोई नाम आज भी सबसे अधिक प्रभावशाली और जनप्रिय माना जाता है तो वह है पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलनाथ का। चाहे कोई भी कांग्रेस का आयोजन हो, सबसे अधिक तालियाँ और जनसमर्थन कमलनाथ को ही प्राप्त होता है। यह न केवल उनकी व्यक्तिगत लोकप्रियता को दर्शाता है, बल्कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं और आम जनता के बीच उनके प्रति विश्वास को भी प्रमाणित करता है। आज जब कांग्रेस मध्यप्रदेश में पुनः सत्ता पाने की दिशा में कार्य कर रही है, तब पार्टी आलाकमान के समक्ष सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि वह किसके नेतृत्व में इस लक्ष्य को प्राप्त करे। ऐसे में कमलनाथ के नेतृत्व को नजरअंदाज करना न केवल राजनीतिक भूल होगी, बल्कि यह कार्यकर्ताओं के मनोबल पर भी नकारात्मक असर डालेगा। आखिर कब कांग्रेस आलाकमान की आंखें खुलेंगी, कमलनाथ की अनदेखी कांग्रेस को भारी पड़ेगी।

तन, मन और धन से कांग्रेस के साथ

कमलनाथ ने जिस समर्पण भाव से मध्यप्रदेश कांग्रेस को खड़ा किया है, वह किसी से छिपा नहीं है। उन्होंने न केवल राजनीतिक रणनीतियों के स्तर पर पार्टी को मजबूत किया, बल्कि अपनी निजी संसाधनों से भी संगठन को सहारा दिया। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचाने में कमलनाथ की दूरदर्शिता और सांगठनिक कुशलता का बड़ा हाथ रहा। (शेष पेज 3 पर)

छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री विजय शर्मा के भाई अजय शर्मा बने प्रदेश के "सुपर" गृहमंत्री!

कवर्धा में अजय शर्मा ने मचा रखा है आतंक

-विजया पाठक

छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री विजय शर्मा का विवादों से चोली दामन का साथ हो गया है। दिन-ब-दिन उनका किसी न किसी विषय को लेकर विवाद खड़ा हो जाता है। नया विवाद उनके बड़े भाई अजय शर्मा को लेकर है। अजय शर्मा अपने क्षेत्र के साथ-साथ पूरे प्रदेश में सुपर गृहमंत्री की तर्ज पर अनैतिक कार्यों को अंजाम देने में जुटे हैं और सरकार के गृहमंत्री विजय शर्मा अपने भाई की काली करतूतों पर आंखें बंद किये हुए हैं। खुलेआम गुंडागर्दी, अवैध वसूली और भ्रष्टाचार के गोरखधंधे का ऐसा जाल फैलाया है कि पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है। यह सरासर गृहमंत्री की सरपरस्ती में फल-फूल रहा है। आरोप है कि मंत्री का भाई अफसरों की पोस्टिंग और ट्रांसफर में खुलेआम पैसे की वसूली कर रहा है। (शेष पेज 5 पर)

सियासी समीकरणों में उलझी एसआईआर

-विजया पाठक

बिहार में इसी वर्ष के अंत में विधानसभा के आम चुनाव हैं उससे पहले ही राज्य में विशेष मतदाता गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को घमासान मच गया है। खासकर विपक्षी पार्टियां एक होकर केन्द्र सरकार पर हमलावर हो गई हैं। और इस प्रक्रिया को एक साजिश के रूप में देख रही हैं। हम जानते हैं कि लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव तब तक संभव नहीं है जब तक कि मतदाता सूची विश्वसनीय न हो। भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार, बिहार में 2003 के बाद से मतदाता सूची का कोई व्यापक पुनरीक्षण नहीं हुआ है। जिसके कारण कई गलतियां और अनियमितताएं देखने में आई हैं। बिहार में करीब 08 करोड़ मतदाता हैं। मतदाता सूची में आमतौर पर कई तरह की त्रुटियां होती हैं- जैसे कि डुप्लिकेट नाम, मृत व्यक्तियों के नाम या अपात्र व्यक्तियों मतदाता सूची में होना आदि जो चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता को प्रभावित करती हैं। पर बिहार में इन सब के अलावा भी बहुत कुछ ऐसा है जो एक स्वस्थ लोकतंत्र में कतई नहीं होना चाहिए। पुनरीक्षण का मुख्य उद्देश्य कई तरह की अनियमितताओं को दूर करना है। जैसे कुछ जिलों जैसे किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया में आधार कार्ड धारकों की संख्या आबादी से अधिक (100% से ऊपर) पाई गई है। जाहिर है कि यहां अवैध अप्रवासी हैं जो निश्चित रूप से फर्जी वोट भी बनवा लिए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकता कि ऐसे फर्जी वोटर्स का काम चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता को भी प्रभावित करना होता है। पुनरीक्षण के माध्यम से, आयोग यह सुनिश्चित करता है कि केवल योग्य भारतीय नागरिक ही मतदान करें, जो संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है। जाहिर है कि इसमें कोई बुराई नहीं है। बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण के विरोध को विपक्ष ने मुद्दा बना दिया है। अगर कायदे से देखें तो नुकसान तो बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को भी हो रहा है। चुनाव आयोग के विशेष मतदाता गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर बिहार की विपक्षी पार्टियां ही सवाल नहीं उठा रही हैं बल्कि आम लोगों के मन में भी कई तरह की आशंकाएं हैं। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) ने एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सड़क पर उतर चुका है। विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' ने आरोप लगाया है कि सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) को लाभ पहुंचाने के लिए यह कवायद हो रही है। हालांकि, निर्वाचन आयोग ने इस आरोप का खंडन किया है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। इस पूरी कवायद के बीच बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है।

एसआईआर में पहले चरण के आंकड़ों में सामने आया है कि लगभग 36 लाख मतदाता या तो लापता हैं या अपने पंजीकृत पते से स्थायी रूप से पलायन कर चुके हैं। इसे लेकर राजनीतिक दल मतदाता सूची की शुद्धता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इसके बाद मतदाता सूची की शुद्धता को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। वहीं देश भर में होने वाले एसआईआर को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। इसे लेकर राजनीतिक दल मतदाता सूची की शुद्धता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पुनरीक्षण के बाद इन मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए जाएंगे। मतदाताओं के इतने महत्वपूर्ण हिस्से का पता लगाने में असमर्थता ने मतदाता पंजीकरण रखरखाव में संभावित प्रणालीगत मुद्दों को उजागर किया है।

बिहार विधानसभा चुनाव में मुश्किल से 4 महीने शेष रह गए हैं। चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने भी तैयारियां शुरू कर दी है और वोटर लिस्ट की समीक्षा की जा रही है। नए सिरे से वोटरों को पहचान पत्र से संबंधित कागजात उपलब्ध कराने की प्रक्रिया विचाराधीन है। आयोग की ओर से दो महीने का समय तय किया गया है लेकिन राजनीतिक दलों ने प्रक्रिया को लेकर कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। महागठबंधन की ओर से न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की बात भी कही जा रही है। बिहार में चुनाव आयोग ने नए मतदाता पहचान पत्र बनाने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। इससे पहले चुनाव आयोग में सही मतदाताओं को चिह्नित करने के लिए प्रक्रिया शुरू की है। प्रक्रिया के तहत पहचान पत्र दिखाने के लिए 11 तरह के कागजात उपलब्ध कराने को मतदाताओं को कहा गया है। 11 विकल्प में आधार कार्ड को विकल्प नहीं माना गया है। चुनाव आयोग की ओर से कहा गया है कि एसआईआर में भाग नहीं लेने वाले मतदाताओं का मतदाता पहचान पत्र भी पहली अगस्त को प्रारूप का प्रकाशन होने के साथ ही अमान्य हो जाएगा। लगभग 22 साल बाद बिहार में मतदाता सूची के सत्यापन की शुरुआत की जा रही है। 25 जून से राज्य में सभी 243 विधानसभा क्षेत्र में 7 करोड़ 89 लाख से अधिक मतदाताओं के लिए नए गणना प्रपत्रों की छपाई एवं घर-घर वितरण की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है।

सात लाख मतदाताओं का दो जगह मिला पंजीकरण

चुनाव आयोग का कहना है कि बिहार के सात लाख मतदाता कई स्थानों पर पंजीकृत पाए गए हैं। वहीं 36 लाख लोग या तो स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गए हैं या फिर उनका पता ही नहीं चला। अब तक 7.24 करोड़ या 91.69 प्रतिशत मतदाताओं से गणना फार्म प्राप्त हुए। चुनाव आयोग ने कहा कि पहले चरण में बिहार की वर्तमान मतदाता सूची (करीब 7.9 करोड़) के 99.8 फीसदी हिस्से को कवर कर लिया है। आयोग ने बयान जारी कर कहा कि मतदाता सूची में 22 लाख नाम ऐसे हैं जो अब जिंदा नहीं हैं। वहीं 07 लाख के करीब नाम दो या दो से अधिक जगहों पर दर्ज पाए गए हैं।

एसआईआर पर क्यों हो रहा विवाद?

पिछले महीने 24 जून को निर्वाचन आयोग ने बिहार में विशेष मतदाता गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का निर्देश दिया था। यह 25 जून से 26 जुलाई 2025 के बीच होना था। चुनाव आयोग का कहना है कि मतदाता सूची में फर्जी, अयोग्य और दो जगहों पर पंजीकृत मतदाताओं को हटाने के उद्देश्य से पुनरीक्षण किया जा रहा है। वहीं विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि चुनाव आयोग इस विशेष गहन पुनरीक्षण के जरिए पिछले दरवाजे से लोगों की नागरिकता की जांच कर रहा है। साथ ही विपक्ष का आरोप है कि इसकी आड़ में बड़े पैमाने पर लोगों से मतदान का अधिकार छीना जा सकता है। हालांकि, चुनाव आयोग ने आश्वासन दिया है कि अगर कोई व्यक्ति मतदाता सूची से बाहर हो जाए, तो इसका मतलब यह नहीं होगा कि उसकी नागरिकता समाप्त हो गई है। चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि कानून और संविधान के तहत उसे यह अधिकार प्राप्त है कि वह नागरिकता से जुड़े दस्तावेज मांग सके, ताकि लोगों को 'मताधिकार' मिल सके।

बिहार में चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे संक्षिप्त गहन मतदाता सूची

संशोधन अभियान को लेकर राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। विपक्षी गठबंधन INDIA ब्लॉक ने इस प्रक्रिया को "गरीब विरोधी, असंवेदनशील और पक्षपातपूर्ण" करार देते हुए विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है। कांग्रेस, राजद और वाम दलों समेत INDIA ब्लॉक के प्रमुख घटक दलों ने आरोप लगाया है कि यह प्रक्रिया 20% से अधिक मतदाताओं को मताधिकार से वंचित कर सकती है।

विपक्षी नेताओं का कहना है कि इस प्रक्रिया से लगभग दो करोड़ मतदाताओं के सूची से बाहर होने का खतरा है। 2003 के बाद ऐसा गहन संशोधन पहली बार हो रहा है। 22 सालों में 4-5 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं- क्या वे सभी गलत थे? अब अचानक इस स्तर का दस्तावेजीकरण क्यों? विपक्ष का मानना है कि बिहार जैसे राज्य में जहां बड़ी आबादी के पास मूलभूत कागजात नहीं हैं, वहां इस प्रकार के दस्तावेज मांगना अनुचित है।

क्या है विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)?

निर्वाचन आयोग ने 24 जून को बिहार के आठ करोड़ मतदाताओं का घर-घर जाकर सत्यापन शुरू करने के लिए एक अधिसूचना जारी की। इस प्रक्रिया के अनुसार, राज्य के सभी मतदाताओं को अपने नाम, पते और फोटो के साथ प्रपत्रों की प्रतियों पर हस्ताक्षर करने होंगे और उन्हें नए फोटोग्राफ और निवास के वैध प्रमाण के साथ वापस भेजना होगा। हालांकि, जिन लोगों के नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं थे, उन्हें विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत अतिरिक्त दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे।

60 लाख मतदाता कौन?

यह भी सवाल है कि वो 60 लाख मतदाता कौन हैं, जिनका नाम लिस्ट से हटाया जाना है। आशंका है कि ये वोटर बिहार के सीमांचल जिले, जो बांग्लादेश और नेपाल से लगते हैं, ऐसे क्षेत्रों के हो सकते हैं, लेकिन यह 1 अगस्त के बाद ही पता चलेगा। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) को 'स्वयं मोटो जांच' शुरू करने का भी अधिकार है, अगर उसे किसी मतदाता का मामला संदिग्ध लगता है। इसके लिए नोटिस 1 अगस्त के बाद जारी किए जाएंगे।

अशोक वानखेड़े ने वंचित वर्गों की आवाज़ को किया बुलंद

कलम के सिपाही

अशोक वानखेड़े भारतीय पत्रकारिता जगत की एक प्रमुख और जानी-मानी हस्ती हैं। उन्होंने अपनी पत्रकारिता से न केवल राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई, बल्कि सामाजिक मुद्दों, खासकर दलित, आदिवासी और वंचित वर्गों की आवाज़ को बुलंद करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दिल्ली में सक्रिय रहने वाले अशोक वानखेड़े लंबे समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं और उन्हें बेबाक, निष्पक्ष और जनपक्षधर पत्रकारिता के लिए जाना जाता है। अशोक वानखेड़े का जन्म महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका प्रारंभिक जीवन संघर्षों से भरा रहा, लेकिन उन्होंने कठिन परिस्थितियों के बावजूद शिक्षा को अपना हथियार बनाया। सामाजिक न्याय और समता के विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने पत्रकारिता को अपना माध्यम बनाया, ताकि वे समाज के हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज़ बन सकें। उन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत एक स्थानीय अखबार से की थी और धीरे-धीरे अपने कौशल, मेहनत और सामाजिक समझ के चलते राष्ट्रीय मीडिया में अपनी मजबूत जगह बनाई। वे कई प्रमुख समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और टीवी चैनलों से जुड़े रहे हैं। उन्होंने लंबे समय तक टीवी पत्रकारिता में भी सक्रिय भूमिका निभाई और अनेक राष्ट्रीय बहसों में अपनी बेबाक राय और तथ्यों के साथ उपस्थिति दर्ज कराई।

अशोक वानखेड़े की पहचान एक ऐसे पत्रकार के रूप में है, जो सत्ता से सवाल पूछने का साहस रखता है और सच को बिना डर के सामने लाता है। वे सामाजिक मुद्दों, खासकर आरक्षण, दलित अत्याचार, सामाजिक असमानता और शिक्षा जैसे विषयों पर खुलकर बोलते हैं। उनकी लेखनी और वक्तव्यों में सामाजिक सरोकार स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। उनकी पत्रकारिता में बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर के विचारों का गहरा प्रभाव है। वे अक्सर अपने लेखों और भाषणों में अंबेडकरवाद की चर्चा करते हैं और समाज में समता, न्याय और बंधुता के सिद्धांतों को स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर देते हैं।

अशोक वानखेड़े ने विभिन्न मंचों पर व्याख्यान दिए हैं और कई सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर जनजागृति का कार्य भी किया है। उन्होंने पत्रकारिता को केवल पेशा न मानकर सामाजिक परिवर्तन का माध्यम माना है। आज भी वे देशभर में हो रहे सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तनों पर पैनी नजर बनाए हुए हैं और सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं। उनकी पत्रकारिता नए पत्रकारों के लिए एक प्रेरणा है। उन्होंने दिखाया है कि ईमानदारी, निडरता और जनभावनाओं की समझ रखने वाला पत्रकार समाज में सार्थक बदलाव ला सकता है। अशोक वानखेड़े न केवल एक पत्रकार हैं, बल्कि वे एक विचारक, वक्ता और सामाजिक योद्धा भी हैं, जिन्होंने पत्रकारिता को जनसेवा का माध्यम बनाया है।

मध्यप्रदेश के संदर्भ में

प्राकृतिक नहीं मानव निर्मित हैं बाढ़.की आपदाएं

-विजया पाठक

हाल ही में मध्यप्रदेश के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से अधिक बारिश हुई। बरसात भले ही सामान्य रही हो लेकिन इसने नदियों में, शहरों में, गावों में कहर बरपा दिया। हालात बद से बदतर हो गये। नदी नालों के किनारे बने घरों के अंदर पानी घुस गया। हजारों लोग बेघर हो गए, फसलें बर्बाद हो गईं। नदी-नाले उफान पर होने से सड़कों से संपर्क टूट गया। वहीं शहरों में हालात बहुत ज्यादा बिगड़ गये। नालों का पानी घरों के अंदर घुसा। बड़े शहरों में तो लोगों के एक-एक मंजिल पानी में डूब गया। खासकर रायसेन, विदिशा, नरसिंहपुर, शिवपुरी, भिण्ड, गुना, श्योपुर, मंडला, डिण्डोरी, नर्मदापुरम आदि जिलों में बाढ़ ने कहर बरपा दिया। इन जिलों के लोगों ने काफी मुसीबतों का सामना किया। आज भले ही इसे लोग प्राकृतिक आपदा के रूप में देख रहे हैं लेकिन सच्चाई में यह विनाशकारी आपदा मानव निर्मित ही है। वर्तमान में प्रदेश में बाढ़ की स्थिति एक गंभीर समस्या बन गई है और यह समस्या साल-दर-साल बढ़ती ही जा रही है। यह स्थिति न केवल प्राकृतिक कारणों से है, बल्कि मानव गतिविधियों के कारण भी बढ़ रही है। अत्यधिक बारिश, नदियों का जल स्तर बढ़ना और बांधों से पानी छोड़ना बाढ़ के मुख्य प्राकृतिक कारण हैं। इसके अतिरिक्त, वनों की कटाई, शहरीकरण और नदियों के किनारों पर अतिक्रमण जैसी मानव निर्मित गतिविधियाँ भी बाढ़ के प्रभाव को बढ़ाती हैं। मध्य प्रदेश में, बाढ़ की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों कारणों पर ध्यान देना आवश्यक है। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, शहरी नियोजन, नदी प्रबंधन और आपदा प्रबंधन के प्रभावी उपाय करके, बाढ़ के खतरे को कम किया जा सकता है। हैं।

मध्य प्रदेश में बाढ़, मुख्य रूप से

अत्यधिक मानसूनी वर्षा और नदियों के उफान के कारण आती है। इसके कारण, सड़कों, घरों और बुनियादी ढांचे को नुकसान होता है, जिससे जानमाल की हानि और आर्थिक विस्थापन होता है। बाढ़ के समाधानों में बेहतर जल प्रबंधन, शहरी नियोजन, और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के उपाय शामिल हैं। बाढ़ एक गंभीर समस्या है जो मध्य प्रदेश में अक्सर होती है। इसके कारणों को संबोधित करना और प्रभावी समाधानों को लागू करना, बाढ़ के प्रभाव को कम करने और लोगों और संपत्ति की रक्षा करने के लिए महत्वपूर्ण है।

मध्य प्रदेश में औसतन 1160 मिमी बारिश होती है। यह बारिश मुख्य रूप से दक्षिण-पूर्वी हिस्सों में अधिक होती है और उत्तर-पश्चिम की ओर कम होती जाती है। अधिकांश वर्षा दक्षिण एशियाई मानसून से जून के महीने में होती है। मध्य प्रदेश में 16 जून को मानसून ने एंट्री ली थी जिसके बाद से लगातार कई क्षेत्रों तेज बारिश का दौर चल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अब तक औसतन 6.8 इंच बारिश हो चुकी है, जो सामान्य से 2 इंच ज्यादा है। मध्यप्रदेश में सीजन में सामान्य रूप से 37.36 इंच बारिश होती है। अब तक 6.8 इंच बारिश हो चुकी है, जो सीजन का 10 प्रतिशत है।

हर साल बढ़ रहा बाढ़ का खतरा

भारत में शहरी बाढ़ का ख़तरा तेजी से बढ़ा है। हाल के वर्षों में कई शहरों में महत्वपूर्ण बाढ़ की घटनाएं दर्ज की गईं। हैदराबाद में 2020 और 2021,नवंबर 2021 में चेन्नई में, 2022 में बेंगलुरु में और अहमदाबाद, जुलाई 2023 में दिल्ली के कुछ हिस्सों में और सितंबर 2023 में नागपुर में बाढ़ आई जिसने कई लोगों को शहर छोड़कर जाने को मजबूर किया। हरियाणा के चंडीगढ़ और गुरुग्राम, बिहार के पटना और गया, महाराष्ट्र में पुणे, राजस्थान में जयपुर और सीकर, मध्य प्रदेश में भोपाल और इंदौर, उत्तर प्रदेश में लखनऊ, केरल के कोच्चि जैसे छोटे शहरों में और पहाड़ी राज्यों में कई जगह जैसे उत्तराखंड में देहरादून और हिमाचल प्रदेश में शिमला को भी हाल के वर्षों में बाढ़ का सामना करना पड़ा है। 2000 और 2019 के बीच, भारत में 321 आपदा की घटनाएं दर्ज की गईं जो चीन (577) और अमेरिका (467) के बाद दुनिया भर के सभी देशों में तीसरे स्थान पर थी। जलवायु परिवर्तन की समस्या का और बदतर होना निश्चित रूप से इस स्थिति को आने वाले समय में और भयावह बना देगा।

असली चुनौती शहरी बाढ़

सामान्य बारिश और भारी बारिश की असली चुनौती है शहरी बाढ़। शहरी बाढ़ की बढ़ती घटनाओं से स्थानीय बुनियादी ढांचे, व्यवसायों और मानव जीवन को काफी नुकसान होता है जिसका स्थानीय, राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं पर आने वाले समय में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। आर्थिक केंद्र होने के कारण शहर की गतिविधि में किसी भी रुकावट के परिणामस्वरूप भारी वित्तीय नुकसान होता है। सड़कें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, बिजली व्यवस्था ठप पड़ जाती है, गंदगी का अंबार लग जाता है, नालों के किनारे बनी झुग्गी झोपड़ी टूट जाती हैं। ऐसी घटनाओं के बाद शहर के बुनियादी ढांचे को फिर से उपयोग करने से पहले पुनर्निर्मित या मरम्मत करना होता है और इसके अतिरिक्त जैसे-जैसे बाढ़ का पानी कम होता है, शहरों को हैजा और मलेरिया जैसी संभावित बीमारियों से बड़ी मात्रा में जूझना पड़ता है। आमतौर पर सड़कों के किनारे पर बने पानी के नालों को फुटपाथ, सड़कों और छतों जैसी सतहों से अतिरिक्त पानी निकालने और इस पानी को एक बड़ी जल प्रणाली में खाली करने के लिए डिजाइन किया जाता है। भारत के अधिकांश शहरों में ये पानी की नालियां या तो नहीं हैं और जो हैं उनका रखरखाव ठीक से नहीं किया जाता है। समय के साथ या तो वे बंद हो जाते हैं या उनकी उपयोगिता बहुत कम हो जाती है। इसके अतिरिक्त, जल निकास प्रणाली भी शहर के विकास के साथ तालमेल रखने में विफल है। असामान्य रूप से भारी बारिश भी आम हो गई है। यह सब घटना स्थानीय परिस्थितियों के साथ मिलकर शहरी बाढ़ की घटनाओं में वृद्धि लाती है। बाढ़ की घटनाएं सामान्य जीवन को बाधित करती हैं, आर्थिक विस्थापन का कारण बनती हैं, बुनियादी ढांचे को नष्ट कर देते हैं और यहां तक कि जानमाल का भारी नुकसान भी हो सकता है। हाल के दशकों में कई बड़े और छोटे भारतीय शहरों को बाढ़ की घटनाओं का सामना करना पड़ा है।

पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के पास है मध्यप्रदेश में कांग्रेस की पुनर्बहाली की चाबी

(पेज 1 का शेष)

उन्होंने ना केवल अनुभवी नेताओं को एक मंच पर लाया, बल्कि युवाओं को भी महत्व देकर पार्टी के भीतर नई ऊर्जा का संचार किया। कमलनाथ ने अपनी योग्यता, आकर्षण और स्थानीय विकास योजनाओं से प्रदेश की जनता को यह विश्वास दिलाया कि कांग्रेस ही वह विकल्प है जो मध्यप्रदेश को आगे बढ़ा सकता है। उनके शासनकाल में शुरू हुई योजनाओं और विशेष रूप से छिंदवाड़ा मॉडल ने पूरे प्रदेश में विकास की नई परिभाषा गढ़ी।

छिंदवाड़ा मॉडल भाजपा के लिए भी प्रेरणा

छिंदवाड़ा, जो कि कमलनाथ का संसदीय क्षेत्र रहा है, आज एक आदर्श विकास मॉडल के रूप में पूरे प्रदेश के सामने प्रस्तुत है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सिंचाई, कृषि और रोजगार के क्षेत्र में किए गए सुधार कार्यों ने छिंदवाड़ा को विकास के मामले में एक अग्रणी जिले में तब्दील कर दिया है। यह मॉडल सिर्फ बुनियादी ढांचे तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें जनभागीदारी, स्थानीय रोजगार सृजन और युवाओं को प्रशिक्षित कर आत्मनिर्भर बनाना जैसे महत्वपूर्ण तत्व भी शामिल हैं। यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी भी इस मॉडल की सराहना करते हुए प्रदेश के अन्य जिलों के लिए इसी तरह की योजनाएं बना रही है। अगर भाजपा को भी यह स्वीकार करना पड़ रहा है कि छिंदवाड़ा मॉडल अनुकरणीय है, तो कांग्रेस को यह समझने में देर नहीं करनी चाहिए कि कमलनाथ ही वह नेता हैं जो इस सोच को राज्य व्यापी बना सकते हैं।

कमलनाथ की गैर मौजूदगी में कम दिखता है जन आंदोलनों का असर

कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या यह रही है कि वह कमलनाथ की सक्रिय भागीदारी के बिना आज तक कोई भी प्रभावी जन आंदोलन खड़ा नहीं कर पाई। चाहे वह किसानों की समस्याएं हों, बेरोजगारी का मुद्दा हो या महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन- हर बार यह देखा गया है कि अगर कमलनाथ नेतृत्व में नहीं होते, तो आंदोलन केवल दिखावटी बनकर रह जाते हैं। कमलनाथ की उपस्थिति ना केवल आंदोलन को जनसमर्थन देती है, बल्कि प्रशासन और सरकार पर भी दबाव बनाती है। उनके पास ऐसा राजनीतिक अनुभव और जनता से जुड़ाव है जो किसी भी आंदोलन को आंदोलन मात्र नहीं, बल्कि जनचेतना में बदलने की शक्ति देता है।

जीतू पटवारी को कमलनाथ का साथ है जरूरी

मध्यप्रदेश कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष जीतू पटवारी एक युवा, ऊर्जावान और जनसंपर्क में दक्ष नेता हैं। लेकिन यह भी सच है कि उन्हें प्रदेश की गहराई से समझ और अनुभव की आवश्यकता है, जो उन्हें कमलनाथ के साथ मिलकर प्राप्त हो सकता है। अगर कांग्रेस को मध्यप्रदेश में भविष्य की राजनीति में मजबूती से खड़ा करना है, तो यह आवश्यक है कि युवा नेतृत्व और अनुभवी मार्गदर्शन का मेल हो। कमलनाथ को दरकिनार करके कांग्रेस प्रदेश में कोई मजबूत रणनीति नहीं बना सकती। जीतू पटवारी को चाहिए कि वे कमलनाथ के साथ मिलकर कार्य करें, उनके अनुभव का लाभ लें और उन्हें संगठन के निर्णयों में सम्मिलित करें।

कांग्रेस आलाकमान को स्पष्ट निर्णय लेने की आवश्यकता

आलाकमान को यह निर्णय लेना होगा कि अगर उन्हें 2028 या उससे पहले के चुनावों में सफलता प्राप्त करनी है, तो उन्हें कमलनाथ को दोबारा कमान सौंपनी होगी- भले ही संगठनात्मक रूप में या चुनावी रणनीति के स्तर पर। कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एक दिशा मिलती है। उनके पास जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं का मजबूत नेटवर्क है, जो चुनाव के समय बूथ स्तर तक काम करता है। साथ ही उनके पास कॉर्पोरेट और निवेशकों से संबंधों का वह अनुभव है जो किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था को संबल दे सकता है।

कमलनाथ ही हैं कांग्रेस की सबसे बड़ी उम्मीद

मध्यप्रदेश में कांग्रेस के पुनरुत्थान की बात हो तो उसमें सबसे पहला नाम कमलनाथ का ही आता है। उन्होंने अपने कार्यकाल में यह सिद्ध किया है कि वे न केवल कुशल प्रशासक हैं, बल्कि जनता के बीच विश्वसनीय नेता भी हैं। उनकी राजनीतिक समझ, सांगठनिक क्षमताएं, विकास के लिए दृष्टिकोण और जनसमर्थन को देखकर यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि अगर कांग्रेस को मध्यप्रदेश में सरकार बनानी है तो कमलनाथ को ही नेतृत्व देना होगा।

कमलनाथ कांग्रेस के लिए केवल एक चेहरा नहीं, बल्कि एक सोच हैं। एक ऐसी सोच जो विकास, समन्वय और जनकल्याण पर आधारित है। यदि कांग्रेस इस सोच को पहचान ले और उसे प्रदेशव्यापी आंदोलन में तब्दील कर दे तो वह दिन दूर नहीं जब मध्यप्रदेश में पुनः कांग्रेस की सरकार बनेगी, और वह सरकार एक स्थायित्व और दूरदृष्टि के साथ शासन करेगी।

सम्पादकीय

ट्रंप का टैरिफ हमला और भारत-अमेरिका की 'दोस्ती' का असल चेहरा

हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और 2024 में फिर से राष्ट्रपति पद के मजबूत दावेदार डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा ने वैश्विक व्यापार जगत में हलचल मचा दी है। ट्रंप का यह फैसला एक बार फिर उनके 'अमेरिका फर्स्ट' एजेंडे की पुष्टि करता है, लेकिन इससे ज्यादा चिंता की बात यह है कि उन्होंने इस निर्णय को उस भारत पर लागू किया है, जिसे वे खुद "11 वर्षों से अपना मित्र" बताते हैं और जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी 'गहरी मित्रता' के चर्चे विश्व मंचों पर होते रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की राजनीति की सबसे बड़ी पहचान यह रही है कि वे अंतरराष्ट्रीय संबंधों को भी एक कारोबारी सौदे की तरह देखते हैं। उनके लिए 'मित्रता' तभी तक मायने रखती है, जब तक वह अमेरिका के हितों को साधती हो। भारत के साथ भी उनकी यही नीति रही है। 2019 में जब ट्रंप अहमदाबाद के 'नमस्ते ट्रंप' कार्यक्रम में शामिल हुए थे, तो विश्व को एक संदेश गया था कि भारत-अमेरिका के संबंध नई ऊंचाइयों पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें "मेरा दोस्त" कहकर संबोधित किया था, और दोनों नेताओं के बीच मेलजोल की तस्वीरों ने वैश्विक सुर्खियां बटोरी थीं। लेकिन अब जब ट्रंप भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं, तो यह सवाल उठना लाजिमी है- क्या यह वही दोस्ती है, जिसके भरोसे भारत ने ट्रंप को गले लगाया था?

ट्रंप की इस घोषणा का सबसे अधिक प्रभाव भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टील, केमिकल, ऑटो पार्ट्स और फार्मा उत्पादों पर पड़ सकता है। ये वे क्षेत्र हैं, जिनमें भारत अमेरिका को बड़ी मात्रा में निर्यात करता है। टैरिफ बढ़ने से भारतीय उत्पाद अमेरिकी बाजार में महंगे हो जाएंगे, जिससे इनकी प्रतिस्पर्धात्मकता घटेगी और निर्यात में गिरावट आ सकती है। इसके अलावा यह निर्णय भारतीय कंपनियों और निवेशकों के लिए चिंता का विषय है, जो पहले से ही वैश्विक मंदी और आपूर्ति श्रृंखला में बाधाओं से जूझ रहे हैं।

यह घटनाक्रम भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक संकेत भी है। एक ओर जहां भारत ने अमेरिकी तकनीक, रक्षा उपकरण और व्यापारिक संबंधों में गहरी दिलचस्पी दिखाई है, वहीं ट्रंप जैसे नेता स्पष्ट कर देते हैं कि अमेरिका की विदेश नीति उसके 'राष्ट्रहित' के अलावा किसी और पर टिकी नहीं होती। भारत ने बीते वर्षों में QUAD, Indo-Pacific रणनीति और अमेरिका से रणनीतिक साझेदारी के नाम पर कई ऐसे फैसले लिए हैं जो चीन की नाराजगी का कारण बने। लेकिन अब ट्रंप जैसे नेता भारत को आर्थिक दंड देकर यह संकेत दे रहे हैं कि उनकी 'मित्रता' सीमित और सशर्त है। डोनाल्ड ट्रंप एक राजनेता कम और कारोबारी ज्यादा हैं। उनकी सोच दीर्घकालिक कूटनीति के बजाय तत्काल लाभ और सौदेबाजी पर आधारित रही है। यह सोच उनके राष्ट्रपति काल में भी दिखी थी, जब उन्होंने ईरान परमाणु समझौते से पीछे हटकर यूरोप और एशिया को चौंका दिया, या फिर जब उन्होंने हैरानी भरे अंदाज में चीन पर टैरिफ लगाए। भारत के साथ उनका यह रवैया दर्शाता है कि व्यक्तिगत समीकरणों पर आधारित कूटनीति हमेशा भरोसेमंद नहीं होती। मोदी और ट्रंप की व्यक्तिगत मित्रता चाहे जितनी भी गहरी हो, अगर वह भारत को आर्थिक नुकसान से नहीं बचा सकती, तो वह केवल मंचीय प्रदर्शन ही कही जाएगी। इस घटनाक्रम से भारत के लिए कई सबक निकलते हैं। पहला- व्यक्तिगत रिश्तों के भरोसे विदेश नीति नहीं चलती। भले ही कोई नेता कितना भी मित्रवत दिखे, अंततः वह अपने देश के लिए काम करेगा, न कि किसी और के। दूसरा- भारत को अपने निर्यात और वैश्विक व्यापार को विविधीकृत करना होगा। यदि भारत केवल अमेरिका जैसे बाजारों पर निर्भर रहेगा, तो टैरिफ जैसे झटके भविष्य में भी संभव हैं। तीसरा- 'आत्मनिर्भर भारत' का लक्ष्य अब केवल नारा नहीं, बल्कि आवश्यकता बन चुका है। घरेलू उत्पादन, नवाचार और वैश्विक गुणवत्ता को बढ़ावा देना ही ऐसा विकल्प है जिससे भारत किसी एक देश की नीतियों पर निर्भर न रहे। ट्रंप द्वारा लगाया गया टैरिफ भारत के लिए एक कड़वा लेकिन जरूरी सच सामने लाता है। यह मित्रता के दिखावे और असल वैश्विक राजनीति के बीच के अंतर को उजागर करता है। यह समय है जब भारत को अपने रणनीतिक हितों को भावनाओं के बजाय वास्तविकताओं के आधार पर पुनर्परिभाषित करना चाहिए।

सियासी गहमागहमी

नेताजी और मछली का जाल

राजधानी भोपाल में भाजपा नेता और मछली कारोबारी की गिरफ्त में आने से न जाने कितनों के चेहरे का रंग उड़ गया है। अभी तक तो नेता लोग मछली के स्वाद में मशगूल थे, लेकिन अब उन्हें लग रहा है कि कहीं ये मछली खुद उन्हें न निगल जाए। जिस तरह से मछली कारोबारी के जाल में सियासत की गंध आने लगी है, उससे कई नेताओं की नींद उड़ गई है। कुछ तो अब मछली की जगह मुंग की खिचड़ी खाने का संकल्प ले चुके हैं — ताकि नाम बेदाग रहे और पेट साफ। खबर ये भी है कि जिन लोगों ने कभी जीवन में मछली पकड़ी तक नहीं, वे भी अब सफाई देने में जुट गए हैं कि "हमारा तो इस तालाब से कोई लेना-देना नहीं है।" भोपाल के राजनीतिक गलियारों में चर्चा गर्म है कि इस कारोबारी की गिरफ्त से निकलते दस्तावेजों में कई बड़े नाम फड़फड़ा रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे पानी से निकली मछलियां। ऐसे में जिनका नाम अभी तक नहीं आया है, वे "भगवान का शुक्र है" बोलते हुए मंदिर-मस्जिद-गिरजाघर सभी जगह माथा टेक रहे हैं। नेताओं की हालत ये हो गई है कि अब वे फाइल से ज्यादा फ्राइंग पैन से डरने लगे हैं। न जाने कौन सी डील, किस तारीख की मछली के साथ तली गई थी। अब देखना ये है कि ये 'मछली प्रकरण' और किस-किसे लीलता है। फिलहाल राजधानी की राजनीति में पानी कम और मछली ज्यादा है और सबको डर है कि कहीं वे भी इस जाल में न फंस जाएं।

इस्तीफा जो हजम नहीं हुआ

देश की राजनीति इन दिनों बड़ी अजीब दौर से गुजर रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के "इस्तीफे की चर्चा" ने जैसे पूरे सियासी हलके में पचने की समस्या पैदा कर दी है। नेता लोग उस बात को अब तक पचाकर नीचे नहीं उतार पाए हैं। कोई नींबू-पानी पी रहा है, कोई हाजमे की गोली खा रहा है, लेकिन अफवाह की कढ़ी है कि उतर ही नहीं रही। असल में हुआ यूं कि उपराष्ट्रपति जी ने कहीं संकेत मात्र दे दिया कि "अगर मैं असंवैधानिक गतिविधियों को अनदेखा करूं तो मेरे इस्तीफे का वक्त आ जाएगा।" बस फिर क्या था। विपक्ष के कुछ नेता इसे पकाकर तवा चढ़ा लाए और सत्तापक्ष के लोग तवे से उठाकर प्लेट में परोसने लग गए। टीवी डिबेट वाले उसे मिर्च-मसाले से इतना चटपटा बना बैठे कि देश के तमाम नेताओं को गैस की शिकायत होने लगी। अब हालात यह है कि किसी दल रोड सुबह उठकर अखबार में ढूंढ़ते हैं। "धनखड़ जी ने इस्तीफा दिया या नहीं?" और जब नहीं मिलता तो थोड़ा उदास होकर कहते हैं- "चलो, कल तक इंतजार करते हैं।" उधर सत्तापक्ष भी भ्रम में है- "अगर वो इस्तीफा दे दें तो नुकसान किसका होगा? हमारा या उनका?" राजनीति में अब मुद्दे कम, अफवाहें ज्यादा और हाजमे की गोलियां सबसे ज्यादा बिक रही हैं।

हफ्ते का कार्टून

ट्वीट-ट्वीट

प्रधानमंत्री जी,
राष्ट्र और सेना आपकी छवि, आपकी राजनीति, आपके PR और प्रचार से बहुत ऊपर है।
यह समझने की विनम्रता रखिए, यह स्वीकार करने की गरिमा रखिए।
आपने अगर निर्णय लेने की क्षमता नहीं थी, तो सेना और राष्ट्र का स्वाभिमान गिरवी रखने का भी आपको कोई अधिकार नहीं था।

-राहुल गांधी
कांग्रेस नेता @RahulGandhi

मैं राजा नहीं हूं और मैं राजा बनना भी नहीं चाहता।
मैं राजा के Concept के खिलाफ हूं।

: नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी जी
-कमलनाथ
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष
@OfficeOfKNath

राजवीरों की बात

भारतीय संस्कृति, धर्म और राष्ट्र सेवा के विचारों से प्रभावित रहीं हैं साध्वी प्रज्ञा सिंह

समता पाठक/जगत प्रवाह

भारतीय राजनीति में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो विवादों, विचारधाराओं और दृढ़ व्यक्तित्व के चलते हमेशा चर्चा में रहते हैं। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ऐसा ही एक नाम हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ीं, संत परंपरा की अनुयायी और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की नेता के रूप में सक्रिय, प्रज्ञा ठाकुर का जीवन तप, संघर्ष, विवाद और राजनीति से घिरा रहा है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का जन्म 2 फरवरी 1970 को मध्यप्रदेश के भिंड जिले के चपराडा गांव में हुआ था। उनका मूल नाम प्रज्ञा सिंह ठाकुर है। वे एक राजपूत परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनके पिता आर.एस.एस. स्वयंसेवक और संस्कृत विद्वान थे। इसी धार्मिक और राष्ट्रवादी वातावरण में उनका पालन-पोषण हुआ। प्रज्ञा बचपन से ही भारतीय संस्कृति, धर्म और राष्ट्र सेवा के विचारों से प्रभावित रहीं। उन्होंने स्नातक तक की पढ़ाई की और इसके बाद अध्यात्म की ओर झुकाव बढ़ता गया। यही कारण रहा कि उन्होंने संन्यास का मार्ग अपनाया और एक समय बाद "साध्वी प्रज्ञा" के नाम से पहचानी जाने लगीं। प्रज्ञा ठाकुर युवावस्था में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़ गई थीं। इसके बाद उन्होंने विश्व हिन्दू परिषद (VHP) और दुर्गा वाहिनी जैसी संगठनों में भी सक्रिय भूमिका निभाई। वे राष्ट्रवादी और हिन्दुत्ववादी विचारधारा की मुखर प्रतिनिधि बनकर उभरीं।

धर्म-रक्षा, गौ रक्षा और लव जिहाद जैसे मुद्दों पर वे शुरू से ही आक्रामक रुख रखती थीं। एक दौर में वे साध्वी ऋतंभरा से भी प्रेरित रहीं और उन्होंने भगवा आंदोलन से जुड़कर अनेक रैलियों और अभियानों में भाग लिया। प्रज्ञा ठाकुर ने विभिन्न संत-आश्रमों में शिक्षा और साधना ली। वे संन्यास धारण करने के बाद मध्यप्रदेश और गुजरात में कई स्थानों पर रही हैं। धर्म और राष्ट्रवाद के सम्मिलन को ही उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य बताया। अपने प्रवचनों और कार्यों से वे कई युवाओं को हिन्दू धर्म की परंपराओं और गौरव से जोड़ती रही हैं।

मालेगांव ब्लास्ट केस और गिरफ्तारीः प्रज्ञा ठाकुर का जीवन सबसे अधिक चर्चा में तब आया जब वर्ष 2008 में महाराष्ट्र के मालेगांव में हुए बम धमाकों में उनका नाम आया। उस ब्लास्ट में 6 लोगों की मौत और दर्जनों लोग घायल हुए थे। 24 अक्टूबर 2008 को ATS (एंटी टेररिज्म स्क्वॉड) ने उन्हें गिरफ्तार किया। आरोप था कि उनकी मोटरसाइकिल का उपयोग मालेगांव धमाके में किया गया था। इसके साथ ही लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित और साधु दयानंद पांडे जैसे नाम भी मामले में सामने आए। प्रज्ञा ठाकुर पर आतंकवाद से संबंधित कई धाराओं में मुकदमा चला। उन्हें मुंबई की अदालत में पेश किया गया। इस गिरफ्तारी और मुकदमे के बाद मीडिया और राजनीति में उन्हें 'हिंदू आतंकवाद' का चेहरा बताकर खूब प्रचारित किया गया, जिससे भारी विवाद खड़ा हुआ। हालांकि दो दिन पहले ही कोर्ट ने इस ब्लास्ट में बनाये गये सभी आरोपियों को मुक्त कर दिया है।

भाजपा ने 2019 के लोकसभा चुनाव में एक बड़ा दांव खेलते हुए भोपाल से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को उम्मीदवार घोषित किया। यह वही सीट थी जहां से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह चुनाव मैदान में थे। इस घोषणा ने सियासी हलचल मचा दी। मीडिया, विपक्ष और मानवाधिकार संगठनों ने भाजपा पर आरोप लगाए कि वह एक "आतंकवाद आरोपी" को टिकट देकर सांप्रदायिक राजनीति कर रही है। इसके बावजूद प्रज्ञा ठाकुर ने प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की। उन्होंने दिग्विजय सिंह को करीब 3 लाख वोटों से हराया। यह भाजपा के लिए न केवल रणनीतिक जीत थी बल्कि 'हिंदू राष्ट्रवाद' की विचारधारा को जनसमर्थन मिलने का भी प्रतीक बन गई।

संसद में कार्य और विवादः सांसद बनने के बाद भी प्रज्ञा ठाकुर विवादों से दूर नहीं रहीं। उन्होंने कई बार ऐसे बयान दिए जो चर्चा और आलोचना के केंद्र में रहे। उन्होंने महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को "देशभक्त" बताया, जिससे संसद में भारी विरोध हुआ और भाजपा ने उन्हें संसदीय समितियों से हटा दिया। उन्होंने 'जादू-टोना', श्राप, और तंत्र-मंत्र जैसे विषयों पर सार्वजनिक बयान दिए, जिससे उनकी छवि एक अंधविश्वासी नेता की बन गई। रक्षा मंत्रालय की समिति में सदस्य बनाए जाने पर विपक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई थी। हालांकि, उन्होंने अपने क्षेत्र में विकास कार्यों, राम मंदिर निर्माण के समर्थन, गौ सेवा और धार्मिक आयोजनों में भी सक्रिय भूमिका निभाई है।

लूटपाट और भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर रहे अजय शर्मा पर गंभीर आरोप

(पेज 1 का शेष)

यह भी कहा जा रहा है कि विभागीय पोस्टिंग का रेट तय कर लिये गये हैं और बिना अजय शर्मा की 'सिफारिश और सुविधा शुल्क' के किसी अधिकारी का तबादला संभव नहीं है। कई अधिकारियों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि मंत्री के भाई के हस्तक्षेप से पुलिसिंग की कार्यक्षमता पर बुरा असर पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में पुलिसिंग व्यवस्था पूरी तरह चरमराई नजर आ रही है। अधिकारी कहते हैं कि गृहमंत्री का फोकस लॉ एंड ऑर्डर पर नहीं बल्कि राजनीतिक मैनेजमेंट और व्यक्तिगत प्रभाव बढ़ाने पर रहा है, जिसका खामियाजा आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। राजधानी रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़, कवर्धा और कोरबा जैसे जिलों में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में निरंतर वृद्धि ने सरकार की संवेदनशीलता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

भाई अजय शर्मा चला रहा गृह मंत्रालय!

सूत्रों का कहना है कि अजय शर्मा सिर्फ गृह मंत्रालय में ही घुसपैठ नहीं कर रहे हैं। वह नगर निगम, आरटीओ, पीडब्ल्यूडी विभाग में भी जमकर अवैध वसूली कर रहे हैं। सभी विभागों के ठेकेदारों का भुगतान अजय शर्मा से मुलाकात के बाद होता है। निश्चित ही इसमें अच्छी खासी रकम कमीशन के तौर पर अजय शर्मा को मिलती है। अजय शर्मा के इस रवैये से ठेकेदार भी काफी परेशान हैं लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नही है। गृहमंत्री का हाथ होने के कारण ठेकेदार भी डरे हुए रहते हैं।

कार्यकर्ताओं से विजय शर्मा का बुरा व्यवहार

कवर्धा क्षेत्र के बीजेपी कार्यकर्ता बहुत निराश हैं। क्योंकि गृहमंत्री विजय शर्मा का व्यवहार बहुत खराब हो गया है। कार्यकर्ताओं से मुलाकात नहीं करते हैं। काम नहीं करते हैं। कार्यकर्ता काम करवाने के लिए आते हैं तो मंत्री कहते हैं काम चंदा करके करवा लो। मैं भी कुछ मदद कर दूंगा। कार्यकर्ताओं ने चुनाव के समय सरपंच और लोगों ने चंदा करके पैसे दिये थे। अब उनके ही काम नहीं हो रहे तो वह नाराज हैं। इसके साथ अब अजय शर्मा का सरकार में दखल हो गया है तो काम बिल्कुल ही नहीं हो रहे हैं।

भाई की करतूतों में गृहमंत्री का खुला संरक्षण

यह भी सच है कि आज जो प्रदेश में गृहमंत्री के भाई अजय शर्मा का काला साम्राज्य खड़ा हो रहा है उसमें विजय शर्मा का पूरा संरक्षण हैं। बिना विजय शर्मा के उसका भाई खुलेआम लूट खसोट नहीं कर सकता है। आज प्रदेश में इसी बात को लेकर चर्चाएं गर्म हैं। सूत्र बताते हैं कि गृहमंत्री को लगने लगा है कि आने वाले समय में उनका चुनाव जीतना मुश्किल है क्योंकि विजय शर्मा की छवि काफी खराब हो चुकी है। यही कारण है कि वह भाई के साथ मिलकर ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहता है। नाम भले ही भाई का आ रहा हो लेकिन पूरा सपोर्ट गृहमंत्री का बताया जा रहा है।

टेंट भी हटा लिया है अजय शर्मा ने

कवर्धा में अजय शर्मा के आवास पर पुलिस का टेंट लगा था, अब उसे हटा दिया गया है क्योंकि यहीं से अजय शर्मा की सारी अवैध वसूली होती है। अजय शर्मा को डर था कि कहीं इसका पता लोगों को न चल सके। पूरा गोरखधंधा यही से संचालित होता है।

आंकड़ों में बयां होती अपराधों की हकीकत

आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि विजय शर्मा के कार्यकाल में राज्य में अपराधों का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। पिछले डेढ़ साल में राज्य में बलात्कार के 2682 मामले दर्ज किए गए, वहीं छेड़छाड़ की 5174 घटनाएं सामने आईं। लूट के मामलों में 38 प्रतिशत, डकैती में 44 प्रतिशत और चोरी की घटनाओं में 62 प्रतिशत का इजाफा हुआ। इन आंकड़ों ने विपक्ष को ही नहीं, सत्ता पक्ष के भीतर भी गृहमंत्री की कार्यप्रणाली पर प्रश्न खड़े करने का मौका दे दिया है। राज्य की कानून व्यवस्था में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, जिसके चलते आम लोगों में भय, असुरक्षा और शासन के प्रति गहरा अविश्वास पनप रहा है। आज छत्तीसगढ़ राज्य की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की चुप्पी क्यों?

राजनीतिक गलियारों में सबसे बड़ा सवाल यही है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आखिर कब तक इस बदहाल स्थिति पर चुप्पी साधे रहेंगे। भाजपा के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री खुद भी गृहमंत्री के कार्य से असंतुष्ट हैं लेकिन राजनीतिक संतुलन साधने के लिए उन्होंने अभी तक कोई कठोर कदम नहीं उठाया। विपक्ष का कहना है कि यदि मुख्यमंत्री ने तत्काल कार्रवाई नहीं की तो आने वाले दिनों में भाजपा सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के अनुसार राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध चरम पर हैं। गृहमंत्री पूरी तरह नाकाम हैं।

किसानों को 10.91 लाख मीट्रिक टन खाद का वितरण

-शशि पांडे

जगत प्रवाह. रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को रासायनिक उर्वरकों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयासरत है। प्रदेश में 14.62 लाख मीट्रिक टन लक्ष्य के विरूद्ध 14.47 लाख मीट्रिक टन रासायनिक खाद का भण्डारण किया गया और किसानों को अब तक 10.91 लाख मीट्रिक टन खाद का वितरण किया जा चुका है। राज्य में डीएपी के व्यवहारिक विकल्प के रूप में नैनो डीएपी की बड़ी संख्या में भंडारण एवं वितरण की व्यवस्था की गई है। राज्य में एनपीके और एसएसपी उर्वरकों के भंडारण और वितरण का लक्ष्य बढ़ाया गया है। कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किसानों को ठोस डीएपी उर्वरक के विकल्प के रूप में नैनो डीएपी अथवा एनपीके और सिंगल सुपर फास्फेट खाद की अनुपातिक मात्रा का उपयोग करने की सलाह दी जा रही है। राज्य सरकार प्रदेश के किसानों को खेती-किसानी की सहूलियत प्रदान करने तथा साहूकारों से चगुंल से बचाने अल्पकालीन कृषि ऋण प्रदान करता है।

राज्य में चालू खरीफ सीजन में किसानों को 5661 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण वितरण किया जा चुका है। यह लक्ष्य का 72 प्रतिशत है। ब्याज मुक्त ऋण वितरण से 12 लाख 76 हजार किसान लाभान्वित हुए है। इस वर्ष किसानों को 7300 करोड़ रूपए अल्प कृषि ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया है। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि खरीफ सीजन 2025 में राज्य में 14 लाख 62 हजार मे.टन. उर्वरक का आबंटन (लक्ष्य) प्रदान किया गया है। इनमें यूरिया का लक्ष्य 7 लाख 12 हजार मीट्रिक टन, डी.ए.पी. का 3 लाख 10 हजार मीट्रिक टन, एन.पी.के. का 1 लाख 80 हजार मीट्रिक टन, पोटाश का 60 हजार मीट्रिक टन तथा सुपर फास्फेट का 2 लाख मीट्रिक टन खाद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 28 जुलाई 2025 की स्थिति में राज्य में यूरिया 6 लाख 50 हजार 941 मीट्रिक टन, डी.ए.पी. 2 लाख 48 मीट्रिक टन, एन.पी.के. 2 लाख 31 हजार 890 मीट्रिक टन खाद का भण्डारण किया जा चुका है। इसी प्रकार पोटाश 77 हजार 976 मीट्रिक टन एवं सुपर फास्फेट 2 लाख 85 हजार 684 मीट्रिक टन, इस प्रकार कुल 14 लाख 46 हजार 539 मीट्रिक टन का भंडारण कर लिया गया है। भंडारण के विरूद्ध अब तक किसानों को 10 लाख 91 हजार 545 मीट्रिक टन रसायनिक खाद का वितरण किया जा चुका है।

महतारी वंदन योजना की 18वीं किश्त के रूप में 647.35 करोड़ रुपये अंतरित

-आनंद शर्मा

जगत प्रवाह. रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महतारी वंदन योजना के अंतर्गत अगस्त माह के पहले दिन 18वीं किश्त की राशि का भुगतान जारी कर दी गई है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रदेश की 69.19 लाख से अधिक महिलाओं को कुल 647.35 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता राशि उनके बैंक खाते में अंतरित की गई है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए इस योजना की शुरुआत मार्च 2024 में की गई थी। अब तक लगातार 18 माहों में 11,728 करोड़ रुपये की राशि प्रदेश की महिलाओं को प्रदाय की जा चुकी है। योजना के अंतर्गत 21 से 60 वर्ष आयु वर्ग की विवाहित, विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रूपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है। महतारी वंदन योजनांतर्गत सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से दी जा रही है।

जिन हितग्राहियों का खाता डीबीटी इनेबल नहीं है वे तत्काल बैंक जाकर आधार लिंक करवायें क्योंकि उनको भुगतान किये जाने पर राशि वापस हो जा रही है तथा इस हेतु उन्हें एसएमएस के माध्यम से सूचित भी किया गया है। यदि किसी हितग्राही को किसी प्रकार की शिकायत हो तो इस पोर्टल में शिकायत करें ऑप्शन में जाकर अपनी समस्या ऑनलाईन दर्ज कर सकती है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने हितग्राही महिलाओं से अपील की है कि वह अपना आधार कार्ड अपडेट करायें, ताकि राशि के भुगतान में किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। ज्ञात हो कि आधार कार्ड को हर 10 वर्षों में अपडेट करना अनिवार्य है। कई हितग्राहियों का भुगतान आधार इनएक्टिव होने के कारण निरस्त हो गया है। ऐसे हितग्राहियों को आधार केंद्र में जाकर पहचान एवं निवास प्रमाण-पत्र के साथ आधार अपडेट कराना आवश्यक है, ताकि आगामी किश्त का भुगतान सुनिश्चित हो सके।

समेरिटंस की छात्रा आरुषि कोरिया में करेगी भारत का प्रतिनिधित्व

-नरेन्द्र दीक्षित

जगत प्रवाह. नर्मदापुरम। साउथ कोरिया में आयोजित होने जा रही कुराश चैंपियनशिप में समेरिटंस विद्यालय की छात्रा आरुषि सल्लाम का चयन भारतीय टीम में हुआ है। आरुषि 33 किलो ग्राम वजन समूह में प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। ज्ञात रहे कि इसके पूर्व आरुषि ने कई राष्ट्रीय कुराश खेल प्रतियोगिता में पदक अर्जित कर चुकी है। यह चैंपियनशिप साउथ कोरिया के चोंग जु शहर में आयोजित होगी। उक्त जानकारी आरुषि की कोच वैशाली तिवारी ने दी। इस उपलब्धि के लिए मध्य प्रदेश कुराश खेल सचिव अंतर्राष्ट्रीय रेफरी राहुल व्यास, विद्यालय के संचालक डॉक्टर आशुतोष कुमार शर्मा, प्राचार्य प्रेरणा रावत, आरके सिंह, राजेंद्र रघुवंशी, सचिन खंपारिया ने शुभकामनाएं व्यक्त कीं।

जिला स्तरीय शालेय कराटे एवं ब्लाक स्तरीय मलखंभ प्रतियोगिता का भव्य आयोजन हुआ

-प्रमोद बरसले

जगत प्रवाह. टिमरनी। शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय टिमरनी में जिला स्तरीय शालेय कराटे प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें विकासखंड स्तर पर चयनित छात्र-छात्राओं ने भाग लिया। यह आयोजन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किया गया था, जिसमें हरदा, टिमरनी और खिरकिया ब्लाक की टीमों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में टिमरनी थाना प्रभारी सुभाष दश्यमिकर एवं उपनिरीक्षक सीताराम पटेल उपस्थित रहे। दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। उन्होंने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा, "हार कर हार मत मानो, मेहनत करो और जीवन में आगे बढ़ो।" शिक्षा विभाग से जिला क्रीड़ा अधिकारी रामनिवास जाट, खेल एवं युवा कल्याण विभाग से ब्लॉक समन्वयक हिना अली उत्कृष्ट विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती ज्योति दुबे कराटे खिलाड़ी मना मंडलेकर सहित जिले के खिलाड़ी उपस्थित रहे। ब्लॉक समन्वयक ने जानकारी दी कि इस प्रतियोगिता से चयनित खिलाड़ी अब संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में हरदा जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। और इसी क्रम में मलखंब प्रतियोगिता का भी आयोजन भी किया गया। इस आयोजन में थानाप्रभारी श्री सुभाष सर के द्वारा मलखंब के प्रतिभागियों का उत्साह वर्धन किया गया इस अवसर पर रितेश तिवारी, मना मंडलेकर, रोहित रहड़वा, देवेश चौहान एवं प्रतीक सर विशेष रूप से उपस्थित रहे। कराटे प्रतियोगिता में निर्णायक की भूमिका अनिश कहार, मोना खरे, करण रामटेक, विकास वर्मा, अभिजीत पचौरे, शालिनी चौहान, महिमा, भावना फरकले एवं इरफान खान का योगदान सराहनीय रहा। इस सफल आयोजन में स्कूल शिक्षा विभाग, खेल एवं युवा कल्याण विभाग तथा तिनका सामाजिक संस्था, टिमरनी का विशेष सहयोग रहा।

गोलीकांड ने मचाया हड़कंप, आधी रात की गोलाबारी से उड़े होश

-बद्री प्रसाद कौरव

जगत प्रवाह. नरसिंहपुर। करेली में बुधवार रात एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे इलाके को हिला दिया, रात करीब 11 बजे जब लोग अपने घरों में सोने की तैयारी कर रहे थे, तभी गोली की आवाज ने शान्ति भंग कर दी। करेली के प्रकाश ठाकुर ने करेली के अमित भाटिया के पैर में गोली मार दी। यह खबर सुनते ही इलाके में सनसनी फैल गई। प्रकाश और अमित के बीच हुए इस झगड़ा की जड़ क्या थी, ये अभी तक साफ नही हो पाया है। लोगों का कहना कि दोनों के बीच छोटी सी बात पर कहा सुनी हुई, जो देखते-देखते इतनी बढ़ गई कि प्रकाश ने अपनी बंदूक निकाल ली और अमित पर फायर कर दिया। गोली अमित के पैर में लगी और वह वहीं मौके पर लहूलुहान हो गया। आसपास के लोग पहुँचे और उसे तत्काल करेली के सरकारी अस्पताल ले गए, जहां अब उसकी हालत स्थिर है। करेली थाना पुलिस हरकत में आ गई, पुलिस ने मौके पर पहुँचकर सबूत जुटाने शुरू किए और प्रकाश की तलाश में छापामार कार्रवाई शुरू कर दी, लेकिन प्रकाश अभी भी फरार है। उसका अभी कोई सुराग नही मिला। करेली में इस घटना के बाद से डर का माहौल है।

वरिष्ठ नेताओं से शिष्टाचार मुलाकातों में ही बीते महत्वपूर्ण 30 दिन

(पेज 1 का शेष)

मुलाकातों का महीना स्वागत, माला और यात्रा

प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद हेमंत खंडेलवाल लगातार प्रदेश के अलग-अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं। यह संगठनात्मक दृष्टि से एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जो किसी भी नए अध्यक्ष के लिए जरूरी मानी जाती है। लेकिन इस "यात्रा कार्यक्रम" में अब तक केवल नेताओं से मिलना, स्वागत समारोहों में शामिल होना, माला पहनना और पारंपरिक भाषणों तक ही गतिविधियाँ सिमटी हैं। आम कार्यकर्ताओं को अभी तक यह अनुभव नहीं हो पाया है कि पार्टी की दिशा या रणनीति में कोई ठोस बदलाव हो रहा है या कोई नया मार्गदर्शन मिल रहा है।

संगठन की सुस्ती और आगामी राजनीतिक चुनौतियाँ

आने वाले महीनों में कई अहम राजनीतिक चुनौतियाँ हैं। नगरीय निकायों के चुनाव, संगठनात्मक पुनर्गठन, लोकसभा चुनाव की तैयारी और विपक्षी दलों की सक्रियता– इन सभी मोर्चों पर पार्टी को निर्णायक रूप से सजग और सशक्त रहना होगा।

यदि प्रदेश अध्यक्ष पद पर ही सुस्ती और अनिर्णय की स्थिति बनी रही तो यह संगठन की कार्यक्षमता पर भी प्रभाव डालेगी। कार्यकर्ताओं का मनोबल घटेगा और जमीनी स्तर पर पार्टी की पकड़ कमजोर हो सकती है। भाजपा की पहचान एक अनुशासन पार्टी के रूप में रही है, जहां नेतृत्व तेजी से निर्णय लेकर कार्यों को गति देता हैं। ऐसे में खंडेलवाल से अपेक्षा है कि वे नेतृत्व की उस परंपरा को निभाएं।

राजनीतिक समझ और संगठन कौशल की कसौटी

हेमंत स्वयं भी लोकसभा सांसद रह चुके हैं और संगठन में वर्षों से सक्रिय हैं। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष का पद केवल अनुभव से नहीं, बल्कि राजनीतिक समझ, संगठनात्मक कौशल, रणनीतिक दृढ़ता और तत्काल निर्णय लेने की क्षमता से संचालित होता है। प्रदेश की भौगोलिक और सामाजिक विविधता को समझते हुए एक संतुलित कार्यकारिणी बनाना, स्थानीय नेताओं की महत्त्वाकांक्षा को साधना, संगठन के पुराने और नए कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय स्थापित करना– ये सभी कार्य आसान नहीं हैं, लेकिन आवश्यक हैं।

दिल्ली का हस्तक्षेप घटेगा या बढ़ेगा?

यह सवाल स्वाभाविक रूप से उभरता है कि क्या खंडेलवाल की नियुक्ति से दिल्ली का हस्तक्षेप प्रदेश की राजनीति में घटेगा? अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है क्योंकि खंडेलवाल न तो पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से कार्य कर पा रहे हैं और न ही उनकी ओर से कोई बड़ा नीतिगत संकेत आया है जिससे यह आंकलन किया जा सके कि वे प्रदेश संगठन को 'अपने ढंग' से चला पा रहे हैं।

सरकार और संगठन का सामंजस्य

भाजपा के लिए सरकार और संगठन का तालमेल हमेशा से उसकी सबसे बड़ी ताकत रही है। लेकिन जब संगठनात्मक ढांचा अधूरा हो, कार्यकारिणी लंबित हो और नियुक्तियाँ रुकी हों तो सरकार भी अकेली पड़ जाती है। कार्यकर्ता भ्रम की स्थिति में आ जाते हैं और विपक्ष को हमले का मौका मिल जाता है।

जनता और कार्यकर्ताओं को परिणाम की अपेक्षा

बिल्कुल, खंडेलवाल के पास अभी भी समय है। एक महीना केवल "परिचय और समझ" के लिए काफी है, लेकिन अब जनता और कार्यकर्ता "परिणाम और दिशा" की अपेक्षा कर रहे हैं। उन्हें चाहिए कि वे अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करें– कार्यकारिणी के गठन से लेकर जमीनी संगठनात्मक मजबूती तक की रूपरेखा घोषित करें। भाजपा का यह विशेषता रही है कि वह समय पर नेतृत्व परिवर्तन करती है और अपेक्षाएं भी उसी के अनुसार रखती है। यदि खंडेलवाल इसे अवसर की तरह लेते हैं, तो यह उनके नेतृत्व की असली परीक्षा होगी।

निःसंदेह हेमंत खंडेलवाल एक अनुभवी नेता हैं, जिनकी ईमानदार छवि और संगठन के प्रति निष्ठा पर कोई संदेह नहीं है। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष पद केवल अनुभव नहीं, कार्यक्षमता की परीक्षा है। अगर यह पद केवल मुलाकातों, स्वागत भाषणों और औपचारिक दौरों तक सीमित रह गया तो भाजपा को आने वाले चुनावी संघर्षों में नुकसान हो सकता है। प्रदेश की भाजपा इकाई को एक सक्रिय, निर्णायक और रणनीतिक नेतृत्व की जरूरत है, जो कार्यकर्ताओं को दिशा दे सके और पार्टी को मजबूती प्रदान करे। कार्यकारिणी का गठन, नियुक्तियों पर निर्णय, संगठन में ऊर्जा का संचार ये अब टालने योग्य कार्य नहीं है। पार्टी आलाकमान पहले भी खंडेलवाल की संगठनात्मक और कार्यक्षमता को परख चुका है। 2020 में जब कांग्रेस के विधायक बीजेपी में आये थे और इन विधायकों को खंडेलवाल के नेतृत्व में ही बैंगलुरू ले जाया गया था। इस काम को इन्होंने बखूबी अंजाम दिया था।

भारत का पर्यावरण संरक्षण में वैश्विक योगदान

पर्यावरण की फिक्र

डॉ. प्रशांत सिन्हा
पर्यावरणविद्

भारत का पर्यावरण के लिए विश्व में योगदान महत्वपूर्ण है। भारत ने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई पहल की हैं और विश्व स्तर पर अपनी भूमिका निभा रहा है। भारत ने अपनी सांस्कृतिक जड़ों से प्रेरणा लेते हुए पर्यावरण संरक्षण को विकास से जोड़ा है, जिससे पूरी दुनिया को एक नई राह दिखाई है। भारत सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिनमें पर्यावरण से संबंधित कई लक्ष्य शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने "मिशन लाइफ" (लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट) अभियान शुरू किया, जिसमें प्रत्येक नागरिक को भागीदारी को अहम माना गया है। भारत ने 2015 में पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग को 2C से नीचे रखना है। भारत जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में एक प्रमुख भूमिका निभा रहा है और देश में कई जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम, 2002 जैसे कानून पारित किए हैं। भारत में लगभग 45,000 पौधों और 81,000 जानवरों की प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत सौर ऊर्जा के क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी है और विश्व में सौर ऊर्जा की सबसे बड़ी क्षमता वाले देशों में से एक है।भारत ने 2070 तक 'नेट जीरो' कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है, जो बेहद महत्वाकांक्षी है, और अपनी राष्ट्रीय जलवायु प्रतिबद्धताओं को तय समय से पहले संशोधित किया। 2021 में कॉप- 26 के दौरान भारत के प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि भारत 2070 तक नेट जीरो इमिशन हासिल करेगा। 2030 तक के लिए एक बड़ा लक्ष्य रखा गया है जैसे 500 जी डब्ल्यू गैर फॉसिल (नवीनीकृत) ऊर्जा क्षमता, ऊर्जा का 50% रिन्यूएबल सोर्सेज कार्बन इंटेंसिटी में 45% कमी, एक अरब टन अनुमानित उत्सर्जन की कटौती इत्यादि। देश फास्ट ट्रैक क्लीन एनर्जी की दिशा में बढ़ चुका है। 2025 तक रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता 220 जीडब्ल्यू पार कर गई है, खासतौर से सोलर विंड और हाइड्रो में तेजी आ गई है। हर साल जी डब्ल्यू नई ग्रीन एनर्जी जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। सोलर रूफ टॉप, ई वी इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन हाइड्रोजन पर जोर दिया गया है। इसपर नीतियां बनाई जा रही है और इसके लिए फंडिंग का इंतजाम भी किया जा रहा है। ग्रीन बॉन्ड, बायो फ्यूल्स एवं ऊर्जा दक्षता का अभियान चलाया जा रहा है। थर्मल पावर प्लांट्स में बायोमास का इंतजाम किया जा रहा है। निवेश और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत तेजी से ग्रीन ट्रांजिशन को अपना रहा है लेकिन निवेश, तकनीक और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी जैसे चुनौतियां भी हैं। भारत ने प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए कई पहलें की हैं, जिसमें 2022 तक एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की प्रतिबद्धता शामिल है। भारत ने विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के लिए "विश्व स्तर पर प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना" विषय को अपनाया है।

भारत ने वृक्षारोपण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किया है और देश में वृक्षों की संख्या बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम चलाए हैंभारत ने वन क्षेत्र को 33% तक लाने का लक्ष्य तय किया है, और पिछले एक दशक में इन्हें काफी बढ़ाया भी है। 'एक पेड़ माँ के नाम' जैसे अभियानों में 142 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए जा चुके हैं, जिससे कार्बन सिंक बढ़ा है और पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत हुआ है। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत ने G20, COP26, इंटरनेशनल सोलर अलायंस और "वन वर्ल्ड, वन सन, वन ग्रिड" जैसे अभियानों का नेतृत्व किया। भारत ने पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का संतुलन बनाकर न केवल अपने देश में, बल्कि पूरी दुनिया में स्थायी विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिए मिसाल कायम की है।

फ्रेंडशिप डे पर विशेष

उत्सव नहीं, जीवन का सम्बल है दोस्ती

जब अगस्त का पहला रविवार करीब आता है तो माहौल में एक अलग-सी खुशी घुलने लगती है। सोशल मीडिया पर बधाइयों की बाढ़ आ जाती है, बाजार रंगीन फ्रेंडशिप बैंड्स से भर जाते हैं और युवाओं के दिलों में दोस्तों के साथ जश्न मनाने की उमंग जाग उठती है। यही तो है फ्रेंडशिप डे का उत्सव। लेकिन इस शोरगुल और चकाचौंध के बीच क्या हमने कभी रुककर सोचा है— क्या दोस्ती सिर्फ इन बाहरी उत्सवों तक सीमित है? क्या दोस्ती का मतलब केवल साथ घूमना, फ़िल्में देखना, पार्टी करना और इंस्टाग्राम पर तस्वीरें साझा करना है? बिलकुल नहीं। दोस्ती का रिश्ता इन सबसे कहीं ज़्यादा गहरा, पवित्र और सार्थक है। दोस्ती का सच्चा स्वरूप मनोरंजन से बढ़कर एक संबल है। आज की युवा पीढ़ी के लिए दोस्ती अवसर साथ वक्त बिताने का एक ज़रिया बनकर रह गई है। वे साथ पढ़ते हैं, खेलते हैं, घूमते हैं और इसे ही दोस्ती का नाम देते हैं। लेकिन यह दोस्ती का केवल बाहरी आवरण है, उसकी आत्मा नहीं। दोस्ती की असली पहचान तब होती है, जब ज़िंदगी की धूप कड़ी हो और हालात मुश्किल। सच्चा दोस्त वह नहीं जो आपकी हर हाँ में हाँ मिलाए, बल्कि वह है जो आपके ग़लत होने पर आपको आईना दिखाए। वह आपकी ग़लती पर पर्दा नहीं डालता, बल्कि उस ग़लती का एहसास कराकर आपको सही राह पर लाने की हिम्मत रखता है। वह आपकी सफलता पर जलता नहीं, बल्कि आपकी कामयाबी को अपनी कामयाबी मानकर खुश होता है। जब आप टूटकर बिखर रहे हों, तो वह आपका हाथ थामकर कहता है, "मैं हूँ ना!"- यह तीन शब्द दुनिया की किसी भी दौलत से बढ़कर होते हैं। यही वह संबल है, जो दोस्ती की नींव को मज़बूत करता है।

आज की बात

प्रवीण कक्कड़
स्वतंत्र लेखक

एक कहानी जो दोस्ती को परिभाषित करती है

दोस्ती की सबसे बड़ी मिसाल हमें भगवान कृष्ण और सुदामा के रिश्ते में देखने को मिलती है। सुदामा ग़रीबी में जी रहे थे और कृष्ण द्वारका के राजा थे। जब सुदामा अपने मित्र से मिलने गए तो उनके मन में संकोच था। उनके पास कृष्ण को देने के लिए सिर्फ मुट्ठी भर चावल थे। लेकिन कृष्ण ने न केवल उन चावलों को दुनिया के सबसे बड़े तोहफे की तरह स्वीकार किया, बल्कि बिना बताए ही सुदामा की हर मुश्किल को दूर कर दिया। उन्होंने सुदामा की ग़रीबी नहीं, उनके मन का प्रेम देखा। यही सच्ची दोस्ती है- जो पद, प्रतिष्ठा और हालात से परे, केवल दिल के रिश्ते को समझती है।

आज के दौर में दोस्ती की ज़रूरत

आज के इस डिजिटल युग में जहाँ हमारे हज़ारों 'ऑनलाइन फ्रेंड्स' हैं, हम असल ज़िंदगी में उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। दिखावे की इस दुनिया में एक ऐसा कंधा मिलना मुश्किल है, जिस पर सिर रखकर आप अपने मन की हर बात कह सकें, बिना इस डर के कि आपको जज किया जाएगा। एक सच्चा दोस्त आपकी बातों को ही नहीं, आपकी खामोशी को भी समझता है। वह आपके अनुभवों से सीखता है और आपको एक बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करता है। वह आपका मार्गदर्शक है, आपका आलोचक है और आपका सबसे बड़ा समर्थक भी। अगर आपका दोस्त आपको किसी बुरी लत से दूर रहने या अपने करियर पर ध्यान देने के लिए टोकता है, तो वह आपका दुश्मन नहीं, बल्कि सबसे बड़ा हितैषी है। बल्कि जीवन भर का सबसे अनमोल और अटूट विश्वास है।

फ्रेंडशिप डे : कुछ रोचक तथ्य और वर्तमान परिदृश्य

फ्रेंडशिप डे की शुरुआत कब हुई?

आधिकारिक तौर पर फ्रेंडशिप डे का विचार पहली बार 1958 में पैराग्वे में 'वर्ल्ड फ्रेंडशिप क्रूसेड' द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इसके बाद 2011 में संयुक्त राष्ट्र की आम सभा ने 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय फ्रेंडशिप डे के रूप में मनाने की घोषणा की।

भारत में अगस्त के पहले रविवार को क्यों मनाया जाता है?

संयुक्त राष्ट्र की घोषणा से पहले ही, कई देशों में फ्रेंडशिप डे मनाने की परंपरा शुरू हो चुकी थी। इसकी शुरुआत 1930 में हॉलमार्क कार्ड्स के संस्थापक, जॉयस हॉल द्वारा की गई थी, जिन्होंने 2 अगस्त को दोस्तों के लिए एक दिन के रूप में प्रचारित किया था। हालांकि यह अमेरिका में सफल नहीं हुआ, लेकिन भारत, बांग्लादेश, मलेशिया और यूएई जैसे कई एशियाई देशों ने अगस्त के पहले रविवार को फ्रेंडशिप डे मनाने की परंपरा को अपना लिया और यह आज भी जारी है।

इसका स्वरूप कैसे बदलता गया?

शुरुआत में लोग एक-दूसरे को ग्रीटिंग कार्ड्स भेजकर फ्रेंडशिप डे मनाते थे। समय के साथ, इसका स्वरूप बदला और हाथों में 'फ्रेंडशिप बैंड' बाँधने का चलन शुरू हुआ, जो दोस्ती के अटूट बंधन का प्रतीक बन गया। आज डिजिटल युग में, यह मुख्य रूप से सोशल मीडिया पोस्ट, स्टेटस अपडेट्स, पार्टियों और गेट-टुगेदर के ज़रिए मनाया जाता है।

फ्रेंडशिप बैंड का क्या महत्व है?

फ्रेंडशिप बैंड सिर्फ एक धागा या बैंड नहीं है, यह एक वादा है, एक प्रतीक है। इसे दोस्त की कलाई पर बाँधना यह दर्शाता है कि आप इस रिश्ते की कद्र करते हैं और हमेशा उसके साथ खड़े रहेंगे। यह दोस्ती के सम्मान और स्नेह का एक सुंदर और सरल इज़हार है।

मौजूदा भारतीय परिदृश्य में फ्रेंडशिप डे

भारत में फ्रेंडशिप डे, विशेष रूप से युवाओं और स्कूली बच्चों के बीच, बेहद लोकप्रिय है। यह एक बड़े व्यावसायिक अवसर में भी बदल गया है। बाजारों में तरह-तरह के गिफ्ट्स, कार्ड्स और बैंड्स की भरमार होती है। कैफे और रेस्टोरेंट्स में विशेष ऑफर्स दिए जाते हैं। जहाँ एक ओर यह दिन दोस्तों के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का एक सुंदर अवसर प्रदान करता है, वहीं दूसरी ओर इसका बहुत अधिक व्यावसायीकरण और डिजिटलीकरण भी हो गया है, जिससे कभी-कभी इसका गहरा और वास्तविक अर्थ पीछे छूट जाता है। दोस्ती कोई त्यौहार नहीं, एक अनुभूति है, जो बिना कहे समझती है, बिना मांगे देती है, और बिना शोर किए जीवन को सहारा देती है। इस फ्रेंडशिप डे पर एक दिन की पोस्ट नहीं, जीवन भर की मौजूदगी का वादा कीजिए। तो इस फ्रेंडशिप डे, एक बैंड बाँधने या पार्टी करने से आगे बढ़ें। अपने उस दोस्त को धन्यवाद कहें, जो आपके लिए हर मुश्किल घड़ी में खड़ा रहा। उससे मिलें, बातें करें और उसे बताएं कि वह आपकी ज़िंदगी में कितना मायने रखता है। दोस्ती को एक दिन के जश्न में न बांधें, इसे जीवन की सबसे बड़ी ताक़त बनाएं। क्योंकि सच्ची दोस्ती एक उत्सव नहीं, बल्कि जीवन भर का सबसे अनमोल और अटूट विश्वास है।

औद्योगिक नीति

अब और अधिक रोजगारपरक, व्यापक और उद्यमों के लिए लाभकारी

श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

स्थानीय युवाओं को रोजगार देने वाले उद्योगों को विशेष अनुदान

आधुनिक खेती से लेकर खिलौना उद्योग तक को मिलेगा बढ़ावा

वस्त्र क्षेत्र में निवेश पर अब 200 फीसदी तक का प्रोत्साहन

ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, रक्षा और एयरोस्पेस सेक्टर को विशेष पैकेज

पर्यटन और होटल व्यवसाय को बढ़ावा

नीति में संशोधन से युवाओं, किसानों, उद्यमियों और निवेशकों को सीधा लाभ

R.O. No. : 13331/ 1

सुशासन से समृद्धि की ओर

Visit us : ChhattisgarhCMO DPRChhattisgarh www.dprcg.gov.in

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक विजया पाठक द्वारा जेयन आफसेट वर्क्स, पुल बोगदा भोपाल 462023 (मप्र) से मुद्रित तथा एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल (मप्र) से प्रकाशित। **संपादक : विजया पाठक।**
RNI-MPBIL/2011/39805 समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एट के तहत जिम्मेदार। (सभी विवादों का न्यायक्षेत्र भोपाल रहेगा।)